पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 17 अग्रहायण, 1933 (श०)
08 दिसम्बर, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—07

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	02
(2) कृषि विभाग	..	..	02
(3) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	03
		कुल योग ..	07

खाद की आपूर्त्ति

15. अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 4 सितम्बर, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''खाद के लिए हाहाकार'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में खरीफ फसल हेतु 7.25 लाख एम०टी० के विरुद्ध मात्र 5.65 एम०टी० यूरिया ही उपलब्ध कराया गया है, जिसके फलस्वरूप किसानों में हाहाकार मचा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को मांग से अधिक खाद की आपूर्त्ति की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाद की आपूर्त्ति मांग के अनुसार कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कचरा प्रबंधन की योजना

16. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--दिनांक 25 सितम्बर, 2011 को पटना से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र के शीर्षक ''उफ ! कहां नहीं है कचरा'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में कुड़े का नियमित उठाव नहीं होने से सड़कों एवं गलियों में कुड़ा का अंबार लगा है;

(2) क्या यह बात सही है कि राजधानी में 2500 से ज्यादा मेनहाल एवं कैचपिट खुले हैं, लेकिन मात्र 350 ढक्कन ही उन्हें ढकने हेतु अंचलों को उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके फलस्वरूप आये दिन दुर्घटना होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खुले मेनहॉल को ढकने की व्यवस्था करते हुए राजधानी में कचरा प्रबंधन की योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का व्यय

17. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी०पी०एल० परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से अनाज खरीद कर खाद्यान्न की आपूर्त्ति हेतु कुल 299.99 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है, यदि हां, तो अबतक उक्त राशि से प्राप्त भौतिक उपलब्धि एवं अवशेष राशि को व्यय करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

किसानों को भुगतान

18. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 24 मई, 2011 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''किसानों का एफ०सी०आई० पर करोड़ों बकाया'' के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 में राज्य में एफ०सी०आई० के माध्यम से खाद्यान्नों के लिए खरीद का 120 क्रय केन्द्र स्थापित होने की जगह मात्र 90 केन्द्रों से ही खरीद हुआ, जिससे किसानों को काफी कठिनाई हुई है;

(1) क्या यह बात सही है कि एफ०सी०आई० के पास 1.79 लाख मिट्रिक टन चावल के विरुद्ध किसानों का 54 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है;

(3) क्या यह बात सही है कि एफ०सी०आई० द्वारा किसानों को उक्त बकाये का भुगतान 7--15 दिनों के स्थान पर 2-3 महीनों के बाद भी नहीं किया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों का बकाया भुगतान की प्रक्रिया ठीक करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्ता कायम करना

19. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा वर्ष 2010-11 में 1807.50 करोड़ की लागत से राज्य में शहरी विकास की 22 योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है, यदि हां, तो इन योजनाओं को समयबद्ध कार्यान्वयन एवं उच्च स्तर की गुणवत्ता कायम रखने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

20. श्री प्रमोद कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "ढाई हजार बोरे बाहर निकाले गये, 10 हजार बोरे गोदाम में होने की आशंका, आयुक्त के ओ०एस०डी० ने की जांच, अनाज जब्ती: पांच गोदाम सील, तीन पर केस" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पकड़े गये अनाज बी०पी०एल० धारी, अन्नपूर्णा, अन्नोदय के अन्तर्गत मोतिहारी विधान-सभा क्षेत्र में पड़ने वाले लाभार्थियों का सर्वाधिक अनाज है जो कालाबजारी बतौर पकड़ा गया है, जिसपर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषकों को ऋण देना

21. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक 44, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा सभी प्रखण्डों में कृषि मेगा ऋण के तहत किसान क्रेडिट कार्ड कैम्प लगाकर ऋण वितरण करने का निदेश बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 में 20 लाख किसानों को ऋण देने की योजना है, जिसमें 10 लाख किसानों को आजतक ऋण नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समय सीमा के अन्दर क्रेडिट कार्ड के तहत कृषकों को ऋण देने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 63-डी०टी०पी०--450